

गुनाह बना दिया गया है। United Naga Council नाम के संगठन ने फिर से पिछले सप्ताह पच्चीस दिन के इस हाईवे बंद का आह्वान किया है, जिस कारण कोई भी जरूरत की वस्तुएं वहां नहीं जा रही हैं। वहां तिरंगा झंडा लहराना मुश्किल हो गया, जब तक कि सुरक्षा सैनिकों के साथ मैं आप तिरंगा न लहराएं। वहां पर जन-गण-मन को आप गा नहीं सकते और इसको स्कूलों में गाना प्रतिबंधित कर दिया गया। United Council of Nagaland जो है, उसको National Socialist Council of Nagaland (Isak-Muivah) ग्रुप का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आह्वान किया है कि We want greater Nagaland जिसमें मणिपुर के हिस्से शामिल करना चाहते हैं और उनका सांप्रदायिक नारा है — Nagaland for Christ. इस कारण जो अन्य हमारे मणिपुरी भाई हैं, उनको वहां बेहद आतंक के साथ मैं सीना पड़ रहा है। वहां सरकार द्वारा सामान्य वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। पिछले छः महीने से लगभग पंद्रह हजार सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और उसके पहले बाईस हजार कर्मचारी चार महीने की हड़ताल पर थे। कोई काम वहां पर नहीं हुआ।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Thank you.

श्री तरुण विजय: वहां के लोग जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली के लोग उनके बारे में चिंतित हैं? क्या वे मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं?

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): सर, मैं इसके साथ एसोसिएट करता हूं।

श्रीमती कुसुम राय (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं इस विषय के साथ अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): सर, मैं स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): सर, मैं इस विषय के साथ एसोसिएट करता हूं।

GOVERNMENT BILLS

The Architects (Amendment) Bill, 2010

MR. CHAIRMAN: We will now take up legislative business. Bills for introduction, Shri Kapil Sibal.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Architects Act, 1972.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I introduce the Bill.

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India)

Amendment Bill, 2010

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI AMBIKA SONI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN: We will now take up The Educational Tribunals Bill, 2010. Shri Kapil Sibal.